शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

विद्यार्थियों में असमंजस, मंडल नहीं ले रहा निर्णय

आरजीपीवी में परीक्षा से पहले होगा मॉक टेस्ट

नवदुनिया खबर पर नजर

भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दसवीं व बारहवीं बोर्ड परीक्षा के संबंध में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। परीक्षा जून में होगी, लेकिन समयसारिणी जारी नहीं की गई है। दसवीं की परीक्षा को लेकर तो विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन इस बारे में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया, लिहाजा विद्यार्थी असमंजस में हैं।

हाल ही में मंडल ने आदेश जारी कर परीक्षा एक माह के लिए स्थगित कर दी थी। आदेश में कहा था कि कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लेकर शीघ्र अवगत कराया जाएगा। ये परीक्षाएं 30 अप्रैल एवं एक मई से प्रारंभ होनी थीं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण इन्हें जून में कराने का निर्णय लिया गया। इस साल दोनों परीक्षाओं में प्रदेश भर से करीब 10 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उधर विगत दिनों स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा था कि 12वीं की परीक्षा अवश्य ली जाएंगी, लेकिन दसवीं परीक्षा के संबंध में एक-दो दिन में निर्णय लिया जाएगा।

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) करीब चार लाख विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा एक से तीस जून के बीच हो सकती है। परीक्षा से पहले प्रदेशभर के विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट लिया जाएगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा होने के कारण विद्यार्थियों से कोई गलती न हो और बाद में वे परेशान न हों। इसके लिए आरजीपीवी राज्य स्तर पर मॉक टेस्ट कराएगा। इसमें सौ फीसद सफलता मिलने के बाद विवि के संबद्ध कॉलेजों में जून से ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी।

इसके पहले 15 से 30 मई तक विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाओं के साथ इंटरनल एग्जाम ऑनलाइन लिए जाने की संभावना है। आरजीपीवी बीई, बीटेक, बीफार्मा और पॉलीटेक्निक के अलावा एमटेक और एमफार्मा प्रथम से अंतिम सेमेस्टर में प्रवेशरत विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा लेगा। 15 मई से प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। एक से बस जून तक अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा, इसके बाद 11 से तीस जून तक शेष परीक्षाएं आयोजित होंगी।

मोबाइल से भी दे सकेंगे टेस्ट

आरजीपीवी ने विद्यार्थियों के लिए घर बैठे परीक्षा देने की व्यवस्था की है। इसमें विद्यार्थी अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट और मोबाइल से भी मॉक टेस्ट दे सकेंगे। मॉक टेस्ट का रिजल्ट भी विद्यार्थियों को उनके मोबाइल पर तत्काल दिखाई देगा। आरजीपीवी 30 जून से रिजल्ट देने की तैयारी में भी है। इसकी शुरूआत अंतिम सेमेस्टर से होगी। इसके बाद शेष परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होंगे।

ऑनलाइन चल रहीं कक्षाएं: आरजीपीवी के पालीटेक्निक विद्यार्थियों की वर्तमान में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान उन्हें ऑनलाइन परीक्षा की सूचना भी दी जाएगी। पहले छठवें, चतुर्थ सेमेस्टर और अंत में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा होंगी।

> कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर जून में सभी कक्षाओं की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। - **डॉ. सुनील कुमार गुप्ता,** कुलपति, आरजीपीवी

अन्य बोर्ड ने दिया दसवीं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन

इसे लेकर विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। साथ ही मूल्यांकन किस आधार पर होगा, यह भी तय किया जाएगा। हालांकि इतने दिन बीतने के बाद भी अब तक न तो मंत्री ने कोई निर्णय लिया और न ही मंडल कोई निर्देश जारी कर रहा है। इस संबंध में शिक्षकों का कहना है कि परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में जो भ्रम एवं चिंता की स्थिति है उसे मंडल तत्काल दूर करें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड सहित अन्य राज्यों ने दसवीं के विद्यार्थियों के लिए जनरल प्रमोशन का निर्णय ले लिया है तो मप्र बोर्ड भी निर्णय जल्द ले।

एंकर स्टोरी | **दसवीं के नियमित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिल सकते हैं नंबर**

दसवीं बोर्ड की परीक्षा पर असमंजस बरकरार, नवमीं-ग्यारहवीं के छात्रों को तिमाही-छमाही परीक्षा के आधार पर मिलेंगे नंबर

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं बोर्ड की परीक्षा पर असमंजस बरकरार है। हालांकि दसवीं बोर्ड के छात्रों की परीक्षा निरस्त हो गई है, लेकिन छात्रों को पास करने के स्वरूप पर विभाग अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। वहीं, नवमीं-ग्यारहवीं के छात्रों को तिमाही व छमाही परीक्षा के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। दोनों कक्षाओं का परिणाम पंद्रह मई तक घोषित किया जाएगा।

कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के कारण स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा नवमीं और ग्यारहवीं की फाइनल परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों का नवंबर में मूल्यांकन किया गया था। इसमें तिमाही परीक्षा के रूप में रिविजन टेस्ट व छमाही परीक्षा ली गई थी। अब कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के कारण 9वीं-11वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे दोनों परीक्षाओं के बेहतर परफार्मेंस के आधार पर दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों

का मूल्यांकन कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार नवमीं के फाइनल परिणाम पांच विषयों में से सर्वश्रेष्ठ के आधार पर जारी किए जाएंगे। यदि वे पांच विषयों में पास होते हैं और कुल छह विषयों में से एक विषय में फेल हो जाते हैं, तो उन छात्रों को पास घोषित किया दिया जाएगा। एक से अधिक विषयों में 33 फीसदी अंक प्राप्त करने में असफल रहने वाले छात्रों के लिए, अधिकतम 10 ग्रेस मार्क्स अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा 9वीं और कक्षा 11वीं परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने का ऑप्शन भी उन छात्रों को प्रदान किया जाएगा, जो फाइनल परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा जो छात्र दिसंबर-नवंबर 2020 या फरवरी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें परीक्षा के लिए उपस्थित होने का एक और मौका दिया जाएगा। यह मौका कोविड 19 से उत्पन्न स्थिति में सुधार होने के बाद दिया जाएगा।

सीबीएसई की तर्ज पर दसवीं के विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन

कोरोना संक्रमण को देखते हुए तीस अप्रैल से शुरू होने वाली दसवीं की परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग रद्द कर चुका है। अब सिर्फ बारहवीं की परीक्षा होगी। दसवीं के विद्यार्थियों को एमपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्पष्ट कर दिया है कि दसवीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड पर विचार किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों की मानें तो नियमित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, जबकि प्राइवेट विद्यार्थियों की परीक्षा करा ली जाए। इस पर हल नहीं निकलने पर सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का विकल्प भी खुला हुआ है।

> दसवीं के विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द हो चुकी है। सीबीएसई की तर्ज पर विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए हैं। जल्द ही इस पर विचार कर दसवीं के विद्यार्थियों के रिजल्ट को लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
>
> इंदर सिंह परमार
>
> राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा मप्र

दूसरी लहर में अप्रैल माह में 6 जिलों में हुई 112 अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों की मौत

सागर संभाग में 1 माह में कोरोना से 100 अध्यापकों की हुई मौत

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर ने किया खुलासा

कमलेश तिवारी, सागर

कोरोना की दूसरी लहर में सागर संभाग के 6 जिलों में एक माह में कोरोना से करीब 100 अध्यापकों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 प्रतिशत शिक्षकों ने कोरोना की दहशत के चलते दम तोड़ दिया है। सागर संभाग सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना व निवाड़ी जिले में बीते एक माह में अध्यापक संवर्ग के 112 लोक सेवकों की मृत्यु होने की पुष्टि संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर ने की है। शिक्षा विभाग में सेवारत लोक सेवक की मृत्यु होने पर आश्रितों को तत्काल ही अनुग्रह राशि दिए जाने के शासन स्तर पर निर्देश है। बावजूद इसके आश्रितों को अनुग्रह राशि देने में लेटलतीफी और लापरवाही को संयुक्त संचालक शिक्षा ने गंभीरता से लिया है। मृत अध्यापक संवर्ग के आश्रितों को शत-प्रतिशत अनुग्रह राशि देने में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छतरपुर व निवाड़ी जिले शीर्ष पर हैं। जबकि शेष 4 जिलों में 48 मामले लंबित हैं और अब तक 6 जिलों में 64 प्रकरणों में आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर मनीष वर्मा ने बताया कि सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ जिले में आश्रितों को अनुग्रह राशि के भुगतान में लेटलतीफी की शिकायतें सामने आ रहीं हैं। आश्रित परिवार को विभिन्न माध्यम से शिकायतें करने के बाद बहुत कठिनाई से राशि

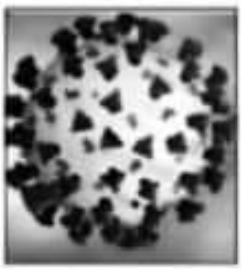

प्राप्त हो रही है, यह निराशाजनक है। वहीं लोक शिक्षण आयुक्त भोपाल ने भी निर्देशित किया है कि विभाग के कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसी दिन अनुग्रह राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश के बाद भी संचालनालय में इस संबंध में शिकायती पत्र प्राप्त होता है तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

संकुल प्राचार्य और बीईओ होंगे सीधे जिम्मेदार

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर ने बताया कि माह अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर में सागर संभाग के 6 जिलों में अध्यापक संवर्ग के 112 लोक सेवकों की मृत्यु होने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। जिसमें जानकारी दी गई है कि करीब 100 अध्यापकों की मृत्यु कोरोना पॉजीटिव होने से हुई है, जबकि 10 से 15 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे भी हैं कि महामारी के इस दौर में तनाव और दहशत में आने से हार्टअटैक सहित अन्य कारणों से भी मृत्यु हुई। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि मृत कर्मचारी के आश्रितों को सूचना मिलने के तत्काल बाद 50 हजार की अनुग्रह राशि का भुगतान आश्रितों को किया जाए, जो कि पूर्व में 25 हजार रुपए थी। बावजूद इसके अनुग्रह राशि देने के कई प्रकरणों में लेटलतीफी और लापरवाही बरते जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई है। सागर संभाग में मृत 112 अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों के प्रकरणों में 64 प्रकरणों को निराकृत कर आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है। जबकि 48 प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। इन प्रकरणों में यह भी देखने में आ रहा है कि जिस कर्मचारी की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है उनके आश्रित भी संक्रमित हैं और इलाजरत है। इसके अलावा आश्रितों के बैंक खाते सहित अन्य दस्तावेज अपडेट नहीं होने के कारण भी प्रकरण लंबित है। जबकि कुछ मामलों में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा भी लापरवाही बरती जा रही है। जेडी श्री वर्मा ने अधिनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि मृत कर्मचारियों के आश्रितों की सूचना प्राप्त होने के दिन ही अनुग्रह राशि उपलब्ध कराएं। वरना राशि नहीं मिलने की शिकायत प्राप्त होने पर संकुल प्राचार्य एवं बीईओ को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार मानकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर कार्यालय से प्राप्त आकड़ों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छतरपुर के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग के 15 कर्मचारियों की एवं निवाड़ी जिला में 6 कर्मचारियों की मृत्यु हुई इनमें से शत-प्रतिशत प्रकरण निराकृत किए है, जबकि सागर जिले में 28 मृत कर्मचारियों में 12 आश्रितों को भुगतान किया गया 16 प्रकरण लंबित है। दमोह में 30 प्रकरणों में 14 को भुगतान 16 लंबित, पन्ना जिले में 16 प्रकरणों में 7 में भुगतान 9 प्रकरण लंबित, टीकमगढ़ जिले में 17 प्रकरणों में 10 आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान की है, जबकि 7 प्रकरण लंबित है।

अभियान जिन लोगों को काढ़ा लेने में संकोच होता है, उन्हें काढ़ा बनाने की विधि बता रहे हैं

संक्रमण से लड़ने शिक्षक घर-घर जाकर दे रहे हैं काढ़ा

श्योपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। शिक्षक आमजन की इम्युनिटी बढ़ाने के लिए सुबह योगा सिखाने के साथ दिन में घर-घर जाकर आयुर्वेदिक काढ़ा बांट रहे हैं।

शिक्षक न केवल लोगों को काढ़ा पीने के फायदे बता रहे हैं, बल्कि उन्हें घर पर ही काढ़ा बनाने की विधि भी बता रहे हैं। जिससे लोग घर पर ही रहकर कोरोना संक्रमण से लड़ सकें। अहम बात यह है, कि काढ़ा बनाने की सामग्री लेने और बांटने में वह किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसका खर्चा वह स्वयं ही वहन कर रहे हैं। श्योपुर से सटे इंद्रापुरी का सहराना प्राथमिक स्कूल में पदस्थ दिनेश साहू ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए अनूठी पहल शुरू की है। साहू शिक्षक के साथ-साथ योग प्रशिक्षक भी हैं।

शहर में लोगों को काढ़ा का पैकेट बांटते शिक्षक दिनेश साहू। • नईदुनिया

यही वजह है कि वह इन दिनों सुबह लोगों को योग के जरिए इम्युनिटी बढ़ाने के तरीके बता रहे हैं तो दिन में काढ़ा बांट रहे हैं। दोपहर में वह लोगों को काढ़ा बांटते हैं। साहू के मुताबिक वह प्रतिदिन 50 से 80 लोगों को काढ़ा बांटते हैं। अब तक करीब 1 हजार से अधिक लोगों को काढ़े के पैकेट बांटे चुके हैं। इंटरनेट मीडिया पर संदेश डालते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए काढ़ा कितना महत्वपूर्ण है।

साहू के मुताबिक जो लोग काढ़ा लेने में संकोच करते हैं वह घर पर ही इसे तैयार कर सकते हैं। वह नीम गिलोय 1 इंच टुकड़ा, काली मिर्च पीसी 1/4, हल्दी 1/4, लौंग 4, इलायची 2, अदरक 1 चम्मच पीसा, दालचीनी 1/4, अजवायन 1 चम्मच, सेंधा नमक 1/4, तुलसी पत्ता 6 या 7 लें। दो लोगों के लिए 200 मिलीमीटर में यह सामग्री डालकर उबालें और जब पानी आधा रह जाए तो ठंडा कर लें।

> कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा रामबाण है। हम रोजाना 70 से 80 लोगों को काढ़ा के पैकेट बांट रहे हैं। अब तक करीब 1 हजार लोगों को काढ़ा बांट चुके हैं।
>
> **- दिनेश साहू**, शिक्षक

कोरोना से मृत शिक्षक, योद्धा करें घोषित

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। देश भर में कोरोना महामारी अपने विकराल रूप में है। प्रदेश में अब तक शिक्षा विभाग के अधिकतर शिक्षक कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, शहपुरा विकासखंड के प्राथमिक शिक्षक विश्वास गर्ग का तो पूरा परिवार ही उजड़ गया। पहले शिक्षक के पिता, फिर माता और अंत में स्वयं शिक्षक विश्वास गर्ग भी कोरोना के प्रकोप से बच न सके। हालात ये है कि भरे पूरे परिवार में अब केवल शिक्षक की पत्नी और वो छोटे-छोटे बच्चे इस आपदा को झेल रहे हैं। राज्य शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से अपील की कि कोरोना से मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का विशेष अभियान चलाया जाए।

राज्य शिक्षक संघ जबलपुर के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र त्रिपाठी ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि अब तक जिले के जो शिक्षक कोरोना से मृत हो चुके हैं। उनमें से अनेक कोरोना रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा लगाई गई ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए हैं। इसके बाद भी सरकार द्वारा शिक्षक संवर्ग को कोरोना योद्धा का दर्जा न मिलने के कारण कोई आर्थिक लाभ नही मिला। हालात ये है कि आश्रित परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है।

तत्काल मिले अनुकंपा: राज्य शिक्षक संघ जबलपुर ने प्रदेश सरकार से मांग की कि पूर्व के मृत और वर्तमान में कोरोना से मृत शिक्षक संवर्ग के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का समयसीमा का विशेष अभियान चलाकर नियुक्ति प्रदान की जाए।

रिजल्ट तैयार करने छात्रों की सालभर की गतिविधियों का ब्यौरा मांगा

पीपुल्स संवाददाता ● ग्वालियर
editor@peoplessamachar.co.in

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं की परीक्षा को कोरोना संक्रमण के चलते निरस्त कर दिया था, लेकिन अब बोर्ड परीक्षा परिणामों को लेकर तैयारी शुरू करने जा रहा है। इसके तहत सीबीएसई द्वारा सभी स्कूलों से विद्यार्थियों की साल भर की गतिविधियों की जानकारियों की रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

सीबीएसई ने स्कूलों को 15 बिंदुओं का एक फॉर्मेट भेजा है। इसमें सालभर हुए प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट आदि की जानकारी मांगी गयी है। इसके आधार पर रिजल्ट की तैयारी की जाएगी। फॉर्मेट में सेक्शनवार छात्रों का नाम, उम्र, पिता

● सीबीएसई ने 10वीं का रिजल्ट तैयार करने 15 बिंदुओं की जानकारी मांगी है

का नाम, जाति, पूर्व परीक्षा का परिणाम की डिटेल्स स्कूलों को भेजना है। स्कूल के टेस्ट में शामिल होने से लेकर टर्म परीक्षा में शामिल होने की जानकारी भी देनी होगी। दसवीं कक्षा की परीक्षाएं एक माह पूर्व होने वाली थी, जिसे रद्द किया जा चुका है। स्कूलों की समस्या है कि लॉकडाउन के चलते शिक्षण संस्थान बंद हैं ऐसे में कैसे जानकारी को जुटाया जाए। कई स्कूलों में स्टाफ खुद ही संक्रमित है तो वहीं स्कूल आने से डर रहे हैं। बता दें कि हाईस्कूल की परीक्षा 4 मई से 14 जून तक होने वाली थीं।

12वीं की परीक्षा को लेकर निर्णय

सीबीएसई ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखकर 4 मई से शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षा 15 जून तक के लिए टाल दी हैं। अभिभावकों की मानें तो जिस तरह 10वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जा रहा है, उसी प्रकार 12वीं के छात्रों को पास किया जाए।

डीपीआई के आदेश को दरकिनार कर स्कूल विद्यार्थियों को दे रहा प्रोजेक्ट

पीपुल्स संवाददाता • जबलपुर
मो.नं.8827460433

शिकायत आने पर डीईओ करेंगे कार्रवाई

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव के कारण बच्चों के मन में भय व तनाव की स्थिति बन गई है। ऐसे में उन पर पढ़ाई का दबाव न बने इसके लिए डीपीआई आयुक्त जयश्री कियावत द्वारा बुधवार को एक आदेश जारी किया गया। जिसके अंतर्गत 1 मई से 31 मई तक पहली से नौंवी व 11 की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित नहीं होंगे और न ही किसी तरह का वर्क या प्राजेक्ट बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन डीपीआई द्वारा जारी आदेश के बाद भी सीबीएसई स्कूल संचालक प्राजेक्ट वर्क के नाम पर बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बनाए हुए हैं।

केस 1 नाम नहीं छापने की शर्त पर संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी ने बताया कि उसे प्रत्येक विषय का प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। जिसका करीब 50 फीसदी वर्क बुक से व अन्य 50 फीसदी इंटरनेट के माध्यम से करना होगा।

केस 2 नाम नहीं छापने की शर्त पर ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल के 9वीं कक्षा के विद्यार्थी ने बताया कि उसे 9 विषय में प्राजेक्ट वर्क दिया गया है। जिसे 1 जून को जमा करना है। विद्यार्थी का कहना है कि टीचर द्वारा दिया गए प्रोजेक्ट वर्क में सिर्फ 40 फीसदी ही बुक का है, बाकि इंटरनेट के माध्यम से कंप्लीट करना होगा।

जानकारी के अनुसार सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुरूवार मतलब 29 अप्रैल को प्रत्येक विषय का प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। जिसे 1 महीने में पूरा करने का समय है। मतलब प्रत्येक विषय के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 से 4 दिन का समय होगा। जिसके बाद 1 जून को प्रोजेक्ट वर्क जमा करने विद्यार्थियों को कहा गया है।

अभी तक किसी तरह की शिकातय नहीं मिली है। डीपीआई के आदेश का पालन नहीं करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-धनश्याम सोनी, डीईओ, जबलपुर

संकुल केन्द्र बेलखाड़ू बना भ्रष्टाचार का अड्डा

कर्मचारी संघ ने की प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग

पीपुल्स संवाददाता ● जबलपुर

editor@peoplessamachar.co.in

पनागर विकासखण्ड के बेलखाड़ू संकुल केन्द्र भ्रष्टाचार व अनियमितताओं का अड्डा बन गया है। संकुल प्राचार्य व लिपिक की मिलीभगत, हठधर्मिता व तानाशाही के कारण संकुल में पदस्थ अध्यापकों के कमोन्नति आदेश जारी होने के लगभग दो वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किया गया है और न ही अध्यापकों को 7वें वेतनमान की एरियर्स की पहली किस्त 31 मार्च तक दिए जाने के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए भुगतान नहीं किया गया है।

इस संबंध में मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रान्तीय संयोजक मुकेश सिंहने बताया कि संकुल में एरियर्स तो दूर, अध्यापकों को हर माह वेतन भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। संकुल प्राचार्य व लिपिक पर कार्रवाई नहीं होने से लंबित प्रकरणों का अंबार लग गया है।

निपटाएं लंबित प्रकरण

संघ के मुकेश सिंह, आलोक अग्निहोत्री, तरूण पंचौली, मनीष चौबे, श्यामनारायण तिवारी, प्रणव साहू, राकेश पाण्डेय, राकेश दुबे, मनीष लोहिया, धीरेन्द्र सोनी, मो. तारिक, प्रियांशु शुक्ला, सुदेश पाण्डेय, मनीष शुक्ला, देवदत्त शुक्ला, सोनल दुबे, ब्रजेश गोस्वामी, विजय कोष्टी, अब्दुल्ला चिस्ती, पवन ताम्रकार, आदित्य दीक्षित, संतोष कावेरिया, जय प्रकाश गुप्ता, सतीश पटैल ने कलेक्टर से मांग की है कि संकुल प्राचार्य व लिपिक पर कार्रवाई कर लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र किया जाए।

प्राइवेट स्कूलों से 3 माह की फीस माफ करवाने की मांग

पीपुल्स संवाददाता ● बेगमगंज

मो.नं. 9993377794

लॉकडाउन के चलते सभी वर्ग के लोगों का काम- धंधा, व्यापार, व्यवसाय बन्द पड़ा है। अभी लोग अपनी दैनिक जरूरतें पूरा कर पाने में भी असमर्थ हो रहे हैं, साथ ही यह लॉकडाउन कब खुलेगा इसकी भी कोई गारण्टी नही है। गारंटी तो इस बात की भी नही है कि बाजार खुलते ही लोगों की आर्थिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में जब स्कूल खुलेंगे तो फीस जमा करना पड़ेगी।

यह एक बहुत बड़ा खर्च होता है, प्रत्येक वर्ग के लोगों के लिए। जोकि अभी काम धंधा ठप्प होने के कारण फीस जमा करना असंभव ह। इसके लिये प्रायवेट स्कूल संचालक तीन माह की फीस माफ करने की कोशिश करें। क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान से अभिभावकों बद्रीविशाल गुप्ता एडवोकेट, चांद मियां एडवोकेट, बजीर खान एडवोकेट, गुफरान अली एडवोकेट, सईद नादां एडवोकेट, विनय खरे एडवोकेट, राजेन्द्र सिंह सोलंकी एडवोकेट, डॉ. जावेद अली, डॉ. नसीम अली, नसीम खान पत्रकार, राकेश श्रीवास, सुभाष रैकवार, हरि साहू पत्रकार, कृष्णा बिट्टू यादव, उत्तम सिंह ठाकुर पत्रकार, मिथलेश दुबे, प. राकेश भार्गव, भरत पटेल इत्यादि सहित प्रायः सभी अभिभावकों ने मांग की है कि सरकार की ओर से एक आदेश जारी करके सभी (प्राइवेट या शासकीय) स्कूल तीन माह की स्कूल फीस छोड़ें या माफ करवाने की व्यवस्था कराएं।

स्कूल में होगा वैक्सीनेशन

अशोकनगर। जिला चिकित्सालय में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के कारण संभावित संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं कोरोना सेम्पल कलेक्शन के लिए स्थान परिवर्तित किया गया है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए सिविज सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ.जे.आर.त्रिवेदिया ने बताया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 01 लवकुश मंदिर के सामने पछाड़ीखेडा में किया जायेगा।

भास्कर

मृत शिक्षकों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति की मांग

भास्कर संवाददाता | पिछोर

कोरोना महामारी के चलते प्रदेश भर में शिक्षकों की हो रही अकाल मौतों पर चिंता जताते हुए मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष आरिफ अंजुम ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को स्मरण पत्र लिखकर समस्त शिक्षक समुदाय को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग की है। उक्त बात मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय प्रवक्ता आनंद लिटोरिया द्वारा बताया गया कि हमारे शिक्षक समुदाय में सैकड़ों मौत हो चुकी हैं जबकि शासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जिस कारण प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा सीएम को मेल किए गए पत्र में आग्रह किया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड 19 की रोकथाम एवं विभागीय गतिविधियों में शिक्षक समुदाय की ड्यूटी प्रत्येक ग्रामों, पंचायतों, नगरों आदि कई जगह पर लगाई गई है। ड्यूटी के दौरान प्रदेश भर में सैकड़ों शिक्षकों एवं कर्मचारियों का निधन होने से उनके आश्रितों को घर, परिवार चलाना दूभर हो रहा है। ऐसे में मृत शिक्षक के परिवार को कोरोना योद्धा अंतर्गत पचास लाख का बीमा एवं उसके परिवार के किसी व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति तत्काल दी जाए। प्रांतीय प्रवक्ता लिटोरिया ने कहा कि पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायत एवं अन्य विभागों की तरह शिक्षा विभाग के मृत कर्मचारियों तथा शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा देकर तत्काल आर्थिक सुविधा मुहैया कराने की मांग की है।

भास्कर

शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की मांग

राज्य शिक्षक संघ और पेंशन संघ ने मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा

भास्कर संवाददाता | शिवपुरी

शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा दीजिए। दिन रात अपनी जिम्मेदारी वह काम कर निभा रहे हैं फिर उनके साथ दोगला व्यवहार क्यों। प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग राज्य शिक्षक संघ और पेंशन संघ के साथ अन्य शिक्षक संगठनों ने की है।

राज्य शिक्षक संघ के स्नेह सिंह रघुवंशी और न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के राष्ट्रीय संयोजक जनक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि कोविड-19 में शिक्षकों की ड्यूटी जिले की सीमा पर, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर और अन्य जगह लगी हुई है। जो दिन रात अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को आज तक कोरोना योद्धा का दर्जा नहीं दिया गया। जो न्याय संगत नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली संघ, राज्य शिक्षक संघ मुख्यमंत्री से मांग करता है कि शिक्षकों और पंचायत विभाग के सचिव व सहायक सचिवों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए। जिससे कुछ अनहोनी होने पर उनके परिवार को भी कुछ सहायता मिल सके। पत्र लिखने वालों में जनक सिंह रावत राष्ट्रीय संयोजक जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत,राज्य शिक्षक संघ के स्नेह सिंह रघुवंशी, विनय सिंह, सुल्तान सिंह ,राजेश सोनी, नीरज मिश्रा, देवेंद्र शर्मा, साजिद शेख, अशोक शर्मा, संदीप कुलश्रेष्ठ आदि शामिल है।

भास्कर

नेशनल पोर्टल की रिपोर्ट में हुआ खुलासाः प्रदेश में छह वर्ष से कम उम्र की 64% बालिकाएं ही जा रहीं स्कूल

बालिका शिक्षा में मध्यप्रदेश देश में 25 वें नम्बर पर

प्रदेश में बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसका कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है। हालात ऐसे हैं कि, 6 वर्ष से कम उम्र की करीब 64 फीसदी बालिकाएं ही स्कूल जा रही हैं, जबकि मध्यप्रदेश देश में 25वें नम्बर पर है।

ग्वालियर • डीबी स्टार

डीबी स्टार को जानकारी मिली कि छह वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं स्कूल नहीं पहुंच पा रही हैं। टीम ने इसकी पड़ताल के लिए नेशनल पोर्टल की रिपोर्ट खंगाली। इस रिपोर्ट के अध्ययन से खुलासा हुआ कि प्रदेश में बालिकाएं शिक्षा की स्थित बदतर होती जा रही है। खास बात यह है कि इस मामले में पड़ोस प्रदेश छत्तीसगढ़ 25वें नम्बर पर है। वहीं, सबसे बेहतर स्थिति केरल की है। जहां 95.4 फीसदी बच्चियां स्कूल गई हैं। वहीं, सबसे खराब स्थिति राजस्थान की है। जहां सिर्फ 54 फीसदी बच्चियां ही स्कूल गई हैं। वहीं, देश की राष्ट्रीय औसत इस मामले में 68 फीसदी से भी ज्यादा है। लेकिन अपना प्रदेश इससे चार फीसदी पीछे चल रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन द्वारा बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे सारे अभियान व योजनाओं का कोई खास असर नहीं पड़ रहा है और स्थिति नहीं सुधर रही है।

राज्यवार शिक्षित बालिकाओं का प्रतिशत

राज्य	शिक्षित बालिकाएं	राज्य	शिक्षित बालिकाएं	राज्य	शिक्षित बालिकाएं
केरल	95.4	हिमाचल प्रदेश	79	ओडिशा	67.8
मिजोरम	91.2	महाराष्ट्र	77.4	छत्तीसगढ़	67.6
गोवा	85	तमिलनाडु	77.2	अरुणाचल प्रदेश	67.1
अंडमान निकोबार	84.7	पंजाब	76	जम्मू कश्मीर	65.6
मेघालय	83	असम	75	मध्य प्रदेश	64
त्रिपुर	81.9	पश्चिम बंगाल	74	उत्तर प्रदेश	63
मणिपुर	81.7	उत्तराखंड	72.7	तेलंगाना	62.2
दिल्ली	81.7	गुजरात	72	आंध्र प्रदेश	62
नागालैंड	81	कर्नाटक	70.7	झारखंड	61.1
सिक्किम	79.7	हरियाणा	70.3	राजस्थान	57.2

100 फीसदी तक शिक्षण का है लक्ष्य

केंद्र सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। साथ ही करोड़ों रुपये खर्च भी किये जाते हैं। वहीं, सभी राज्यों को 100 फीसदी तक शिक्षण व्यवस्था करने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन देशभर में एक भी राज्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया है।

राष्ट्रीय औसत से भी 5% पीछे

रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 6 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को शिक्षा देने के मामले में जहां देश की राष्ट्रीय औसत 68.8 फीसदी है। जबकि मध्यप्रदेश की औसत इस मामले में 64 फीसदी है। यानि हमारा प्रदेश राष्ट्रीय औसत से भी लगभग पांच फीसदी पीछे चल रहा है। जबकि यहां तमाम योजनाओं का संचालन करने का दावा किया जाता है।

भास्कर

नई व्यवस्था... उच्च शिक्षा विभाग ने लिया फैसला

निजी कॉलेजों में फैकल्टी रखने के लिए बनेगा सिलेक्शन सिस्टम

इंदौर/ भोपाल | DBStar

प्रदेश के उच्च शिक्षा से जुड़े प्राइवेट कॉलेजों में फैकल्टी रखने के लिए केंद्रीयकृत चयन प्रणाली बनेगी। प्राइवेट कॉलेजों में पदस्थ शिक्षकों के बार-बार संस्थान बदलने की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी के साथ कई बार प्राइवेट कॉलेज भी उनके यहां पदस्थ फैकल्टी के संबंध में सही जानकारी नहीं देते हैं। प्राइवेट कालेजों में हर साल छात्रों के दाखिला लेने के दौरान कई बार फैकल्टी बीच में ही संस्थान बदल बदल लेती है। हाल में स्थायी समिति की बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब शिक्षकों का स्थायी रूप से चयन और नियमित रूप से काम करने की स्थिति नहीं मिलती है। इस वजह से बड़ी संख्या में शिक्षक नौकरी छोड़ देते हैं या दो-तीन साल में कार्यस्थल बदल लेते हैं।

तीन कैटेगरी : काम का ऐसे हुआ बंटवारा

1- पीएचडी :	2- केवल नेट/	3- पीजी
शिक्षण, अनुसंधान निदेशक व मूल्यांकन आदि का काम कर सकते हैं।	सेट : शिक्षण व मूल्यांकन का काम कर सकते हैं।	55% अंक के साथ : केवल शिक्षण कार्य करेंगे।

यूजीसी में हर साल होगा पंजीयन और अपडेशन

पहली और दूसरी श्रेणी के शिक्षकों की अनुपलब्धता होने पर ही तीसरी श्रेणी के शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसमें यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी अपना पंजीयन करवा सकेंगे। यह पंजीयन हर साल अपडेट किया जाएगा। जो अभ्यर्थी एक बार इसमें पंजीयन करवाएगा उसे यूनिक आईडी मिलेगा। इस यूनिक आईडी से पंजीकृत सिस्टम से कालेज भी इन्हें रख सकते हैं। गौरतलब है कि शिक्षकों के संबंध में कोड 28 का कई कॉलेज पालन नहीं करते हैं। नए सिस्टम इसे इनकी मॉनीटरिंग हो सकेगी। इस सिस्टम में निर्धारित वेतनमान शिक्षकों को देना होगा। निजी कॉलेजों में फैकल्टी को रखने के लिए पूर्णकालिक, अंशकालिक, किसी एक विषय को पढ़ाने की तय समय अवधिक के लिए योग्य शिक्षकों का राज्य स्तरीय पैनल तैयार होगा।

बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड ईयर की परीक्षाएं स्थगित, 5 मई तक भराएंगे फार्म

ग्वालियर | जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा बीए, बीएससी और बीकॉम थर्ड ईयर की परीक्षाएं 1 मई से आयोजित की जानी थीं। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जेयू प्रशासन ने परीक्षा स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही यूजी फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा फार्म भरने का एक और मौका दिया है। अब छात्र-छात्राएं 5 मई तक परीक्षाएं फार्म भर सकेंगे। इससे पहले परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल थी। लेकिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह गए थे। जिसके चलते छात्रों को परीक्षा फार्म भरने का एक और मौका दिया गया है। हालांकि अब परीक्षाएं ऑफ लाइन होंगी या फिर ओपन बुक पद्धति से इसके अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

कॉलेजों ने कमियां दूर नहीं की, तो सीटों में होंगी कटौती

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

सरकारी, प्राइवेट इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। अब एआईसीटीई ने नियमों का पालन नहीं करने पर कॉलेज और पॉलीटेक्निक के सत्र 2021-21 की सीटों में कटौती करने का निर्णय लिया है। कमियों की पूर्ति के लिए एआईसीटीई ने 30 जून तक समय दिया है। प्रदेश में सागर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर और नौगांव सहित एक दर्जन इंजीनियरिंग और 69 पॉलीटेक्निक कॉलेज हैं। एआईसीटीई ने गत वर्ष एक्शन लेते हुए सीटों में कटौती कर दी थी, लेकिन शासन ने एक साल में मापदंडों की पूर्ति का पत्र भेजकर सीटों को बचा लिया था। अभी तक वे अपनी खामियों को दूर नहीं कर पाए हैं। इसलिए एआईसीटीई चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे ने पत्र जारी कर कहा है कि मापदंडों का पालन नहीं करने पर संस्थानों की कुल सीटों में कटौती की जाएगी।

न फैकल्टी है और न सुविधाएं: इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक कॉलेजों में 48 से 58 फीसदी वैकेंसी बनी हुई है। इसके अलावा क्लास रूम, लैब, उपकरण, स्टाफ रूम, कॉमन रूम और अधोसंरचना की कमियों को समय रहते शासन द्वारा पूरा नहीं किया गया, तो कॉलेजों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। 30 जून तक का समय है, उसके बाद मापदंड पूरे नहीं मिले सीटों में कटौती की जाएगी। **-अनिल सहस्त्रबुद्धे**, चेयरमैन, एआईसीटीई

एनएलआईयू : रिसर्च प्रोजेक्ट और केस स्टडी के आधार पर होंगे सेमेस्टर एग्जाम

20% से अधिक नकल मिली तो रिजेक्ट होगा प्रोजेक्ट

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) द्वारा इस बार भी थ्यौरी एग्जाम के बजाय स्टूडेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट के आधार पर नंबर देकर डिग्री दी जाएगी। परीक्षाओं में विद्यार्थियों को आठ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट से जुड़ी केस स्टडी देनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन वायवा होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट 27 मई तक जमा करने हैं। इसके बाद रिजल्ट जारी होंगे। लेकिन यदि स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में 20 प्रतिशत

से अधिक नकल मिली, तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

15 पैरामीटर के आधार पर होगा स्टूडेंटस का वैल्यूएशन: रिसर्च पेपर के आधार पर सेमेस्टर एग्जाम कराने के लिए एनएलआईयू ने 15 पैरामीटर तैयार किए हैं। इस आधार पर विद्यार्थियों का वैल्यूएशन किया जाएगा। पूर्व में थ्यौरी एग्जाम में विद्यार्थियों को 70 अंक और प्रोजेक्ट के 30 अंक दिए जाते थे। वर्तमान में उन्हें रिसर्च पेपर के 70 और वायवा में 30 अंक दिए जाएंगे। सभी 15 पैरामीटर पर खरे उतरने के बाद ही विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत अंक दिए जाएंगे।

यह होगा वैल्युएशन का आधार : एलएलएम, बीएएलएलबी और एमसीएलआईएस के अंतिम सेमेस्टर के लिए रिसर्च पेपर जमा कराए जा रहे हैं। बताया गया है कि सभी रिसर्च का लाइब्रेरी में प्लेगरिज्म टेस्ट किया जाएगा। इसमें कितनी नकल है और कितने प्रतिशत नया है, इसकी रिपोर्ट संबंधित प्रोफेसर के पास जाएगी। उसके आधार पर वैल्यूएशन कर प्रोफेसर स्टूडेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर वायवा लेंगे।

पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के दौरान रिसर्च प्रोजेक्ट के आधार पर स्टूडेंट्स का सुरक्षित वैल्यूएशन कराया था। इस बार उसी पैटर्न पर मूल्यांकन किया जा रहा है। लेकिन इस बार कई चीजें नई जोड़ी गई हैं। 20 प्रतिशत से अधिक नकल मिलने पर प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

डॉ. वी विजयकुमार, कुलपति, एनएलआईयू

जेयू के हेल्थ सेंटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर और सीटी स्कैन मशीन लगाने की मांग

- दो कर्मचारी और दो अतिथि विद्वानों की कोरोना से मौत हो चुकी है, कई कर्मचारी संक्रमित हैं

पीपुल्स संवाददाता • ग्वालियर

editor@peoplessamachar.co.in

जीवाजी विवि में कोरोना के कारण दो कर्मचारियों और दो अतिथि विद्वानों की मौत हो चुकी है साथ कई कर्मचारी और प्रोफेसरों के पत्नी बच्चे कोरोना संक्रमित हैं। इसे लेकर विवि के अधिकारी, प्रोफेसर और कर्मचारी डरे-सहमे हैं। विवि तृतीय श्रेणी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अरविंद सिंह भदौरिया ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए विवि को बंद करने की मांग विवि प्रबंधन से की है मगर इस पर विवि प्रबंधन ने निर्णय नहीं लिया है। विवि के प्रो. केएस ठाकुर ने कोरोना संक्रमण पर चिंता जताते हुए विवि के वॉट्सएप ग्रुप पर विवि के हेल्थ सेंटर पर सीटी स्कैन मशीन और 10 ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम करने की मांग उठाई है ताकि विवि परिवार के किसी सदस्य की तबियत बिगड़े तो उसे तत्काल हेल्थ सेंटर पर इलाज मिल सके। विवि में 600 से अधिक अधिकारी, प्रोफेसर और कर्मचारी कार्यरत हैं।

हेल्थ सेंटर को कोविड सेंटर में तब्दील करने पर पत्र लिखा

जानकारी के अनुसार जेयू कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला ने विवि के हेल्थ सेंटर को कोविड सेंटर में तब्दील करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। विवि के कार्यपरिषद सदस्य कोरोना संक्रमण को लेकर विवि के जिम्नेजियम हॉल, मल्टीआर्ट कॉम्पलेक्स को कोविड सेंटर बनाने की मांग वॉट्सएप ग्रुप पर उठाई है।

इनका कहना है

हेल्थ सेंटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर और सीटी स्कैन मशीन के इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही विवि के अधिकारी, प्रोफेसर और कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। पहले फेज में 900 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर वैक्सीन के लिए पेमेंट करना पड़ा तो विवि इसके लिए भी तैयार है। वैक्सीन लगने के बाद लोग सुरक्षित तो महसूस करेंगे।

प्रो. उमेश होलानी, रेक्टर जेयू

इंजीनियरिंग कॉलेजों को संबद्धता के लिए 30 तक आवेदन करना होगा

ग्वालियर। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एसआईसीटीई) ने इंजीनियरिंग कॉलेजों को सत्र 2021-22 की संबद्धता देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉलेजों को मान्यता निरंतरता के लिए 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एआईसीई द्वारा आवेदन आने के बाद निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए निरीक्षण भौतिकरूप के बजाए ऑनलाइन कराया जाएगा। कॉलेजों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संबद्धता निरंतरता व सीटों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक कोर्सों की सीटों के अनुसार कॉलेज में सुविधाएं नहीं होने पर सीटों में कटौती होगी।

मापदंड पूरे नहीं होने पर सीटों में कटौती होगी

जेयू ने कॉलेजों को बिना निरीक्षण के संबद्धता दी: जेयू प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखकर पांच साल से अधिक पुराने कॉलेजों को सत्र 21-22 की संबद्धता बिना निरीक्षण के ही दे दी है। सत्र 201-21 और 21-22 में नए कॉलेजों का ही निरीक्षण कराया जाएगा साथ ही एनसीटीई के कोर्स चलाने वाले कॉलेजों का निरीक्षण स्थगित कर दिया है।

दैनिक भास्कर
भोपाल 30-04-2021

दो महीने में कोरोना ड्यूटी में लगे 726 शिक्षकों की मौत, 2845 संक्रमित

सिस्टम में लापरवाही का संक्रमण...

फिर भी सरकार इन्हें नहीं मान रही कोरोना वॉरियर्स; न इलाज में सरकारी मदद और न मुआवजे का प्रावधान

छिंदवाड़ा में सर्वाधिक 83 शिक्षकों की मौत, उज्जैन में 61 और सिवनी में 47 मौतें

अनित गुप्ता | भोपाल

प्रदेशभर में कलेक्टरों के निर्देश पर कोविड ड्यूटी में जुटे करीब साढ़े चार हजार शिक्षकों में से बीते दो महीने में 726 की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। जबकि 2845 शिक्षक संक्रमित हैं। लेकिन फिर भी सरकार इन्हें कोरोना वॉरियर नहीं मानती। क्योंकि शिक्षक राज्य सरकार की कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल नहीं हैं, ऐसे में न तो उन्हें इलाज के लिए सरकारी मदद ही ठीक से मिल पा रही है, न ही परिजनों को नौकरी या मुआवजा मिल पाएगा। ऐसे में शिक्षा विभाग के अफसर भी घबराए हुए हैं, उनका कहना है कि मृत शिक्षकों की संख्या बढ़कर 900 से अधिक हो सकती है, पुलिस, राजस्व या नगरीय निकाय के कर्मचारियों की तरह शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को मदद नहीं मिलने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।

गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्कूल टीचर और प्रिंसिपल्स को डोर-टू-डोर सर्वेक्षण, सैंपल कलेक्शन, जांच केंद्र, कंटेनमेंट एरिया के सुपरविजन और चेक पोस्टों में यात्रियों व वाहनों की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। कई जिलों में बड़े अस्पतालों में आरआई-पटवारी के साथ भी इन्हें तैनात किया गया है। शेष | पेज 6 पर

मौत के आंकड़ों के ट्रैकिंग सिस्टम पर अटकी सरकार

मौतें हुई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी का कहना है कि यह बात सही है कि कोरोना से शिक्षकों की मौतें हुई हैं, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। विभाग ने महामारी में जान गंवाने वालों के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। ताकि निधन के बाद परिवार को तत्काल बाकी का पेमेंट हो सके। मार्च-अप्रैल माह में कोविड ड्यूटी से जुड़े सर्वाधिक 83 शिक्षक छिंदवाड़ा में मरे हैं। इसके बाद उज्जैन में 61 और सिवनी में 47 शिक्षकों की मौत हुई है। कोविड योद्धा कल्याण योजना सिर्फ 31 मई तक ही लागू है। इस योजना में शामिल कोविड वॉरियर का के इलाज के संपूर्ण खर्च सरकार उठाती है। इसके अलावा मौत होने की स्थिति में परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्रावधान है।

इन जिलों में सर्वाधिक शिक्षक संक्रमित

किस वर्ग के कितने कर्मचारी संक्रमित

वर्ग	संक्रमित	निधन
अधिकारी	29	3
कर्मचारी	136	44
प्राचार्य	119	24
शिक्षक	2561	655

पुलिसः 1200 संक्रमित, 24 की मौत, बिजली कंपनी में 150 से ज्यादा की मौत

कोरोना वॉरियर्स में शामिल पुलिस जवान भी संक्रमण की चपेट में हैं। महकमे में जनवरी 2021 से लेकर 28 अप्रैल तक 1200 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। इनमें से 24 की मौत हो चुकी है। संक्रमित होने वालों में ज्यादातर ऐसे हैं, जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। इसके अलावा बिजली कंपनी के अफसरों के मुताबिक बीते दो महीने में कोरोना संक्रमण से उनके 150 से अधिक कर्मचारियों की मौत हो चुकी है।

दैनिक भास्कर भोपाल 30-04-2021

34 दिन तक सिर्फ 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 18738 स्लॉट

वैक्सीन की शॉर्टेज

मप्र में 1 मई से शुरू नहीं होगा 18+ वालों का टीकाकरण

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

राजधानी में 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन कार्यक्रम में अभी भी 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। अगले 34 दिन में एक भी स्लॉट 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए ओपन नहीं किया गया है। 29 अप्रैल की शाम तक जो स्लॉट राजधानी में बुक हुए उनमें केवल 12 दिन ही वैक्सीनेशन होना दिखाया है। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक उम्र के 18738 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को फिलहाल इंतजार करना होगा। फिलहाल सरकार के पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि फिलहाल प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का टीकाकरण ही जारी रहेगा। 3 मई तक करीब 4 लाख वैक्सीन आने की संभावना है। इसमें 3 लाख कोविशील्ड और 1 लाख कोवैक्सीन आएगी। 1 मई से वैक्सीनेशन अस्पताल की बजाए आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, स्कूल और कम्यूनिटी हॉल में किया जाएगा। फिलहाल भोपाल जिले में 45+ वालों के लिए 56 वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं तो वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए अब तक कोई सेंटर तय नहीं किया। शेष | पेज 6 पर

प्रदेश में बीते 5 दिन से सेकंड डोज वालों को लगाई गई दोगुनी वैक्सीन

प्रदेश में वैक्सीन की शार्टेज के कारण अब दूसरी डोज वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। पांच दिन में डोज-2 वाले 97747 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है, जबकि डोज-1 वाले सिर्फ 56112 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई है। 25 अप्रैल के बाद से डोज-2 वालों को वरीयता दी जा रही है। जबकि इससे पहले डोज-1 वालों का आंकड़ा डोज-2 से लगभग दो गुना अधिक था। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर से डोज-1 लगवाने पहुंचने वालों को 1 मई के बाद आने को कहा जा रहा है।

नाकाफी होंगे प्रदेश में 45 लाख डोज

प्रदेश में 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन शुरू करने का टारगेट है, इसके लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। जबकि केंद्रीय आपूर्ति अलग से जारी रहेगी। लेकिन राज्य की जरूरत के हिसाब से यह नाकाफी है। क्योंकि प्रदेश में अभी तक 60 लाख डोज तो सिर्फ उन लोगों को ही लग जाएंगी। शेष | पेज 6 पर

राज्यों के हाल... कई राज्यों ने कोरोना टीकाकरण आगे बढ़ाया

नई दिल्ली | टीके की कमी की वजह से महाराष्ट्र, झारखंड सहित कई राज्यों ने टीकाकरण आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं, केंद्र का दावा है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अभी तक 16.16 करोड़ वैक्सीन डोज मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं। अगले तीन दिनों में 20 लाख डोज और मुफ्त उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र : टीके की सबसे ज्यादा कमी महाराष्ट्र में है। यहां रोजाना टीकाकरण की संख्या घटकर 1.50 लाख तक आ गई है। राज्य में 1.55 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। 18 से 45 साल वालों के लिए टीकाकरण अभियान मई के अंत तक शुरू होने की संभावना जताई गई है। शेष | पेज 6 पर

स्वास्थ्य विभाग ने आदेश किए जारी

Bsc नर्सिंग और JNM के फाइनल ईयर छात्र करेंगे कोरोना में ड्यूटी

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

कोरोना संकट में मरीजों का इलाज करने के लिए स्टाफ की अस्पतालों में भारी कमी पड़ रही है। लगातार स्टाफ की कमी के कारण मरीजों के इलाज में परेशानी को देखते हुए अब बीएससी नर्सिंग और जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की इमरजेंसी कोविड ड्यूटी लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की अपर संचालक (नर्सिंग) सपना लोवंशी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

मिलेगी 20 हजार सैलरी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक छह जिलों में इन नर्सिंग स्टूडेंट्स की पोस्टिंग सीएमएचओ के अधीन की गई है। इनमें ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, कटनी, विदिशा एवं बैतूल में 30-30 स्टूडेंट्स की ड्यूटी 31 मई तक के लिए लगाई गई है। इस दौरान इन स्टूडेंट्स को स्टाफनर्स के समान 20 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। सीएमएचओ इनकी ड्यूटी कोविड कंट्रोल ऑपरेशन में लगा सकेंगे। इन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा साधन पीपीई किट मुहैया कराए जाएंगे।

3 दिनों में नहीं पहुंचने पर होगी एस्मा की कार्रवाई

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार तीन दिन के भीतर नर्सिंग स्टूडेंट्स को अपनी ज्वॉइनिंग देनी होगी। यदि छात्र नहीं पहुंचे तो उनपर एस्मा के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।

कॉलेजों को एक माह के अंदर भेजना होगी पूरी डिटेल

280 निजी कॉलेजों में फैकल्टी नहीं, संबद्धता खत्म करेगा BU

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त 280 कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन और प्राचार्यों नहीं होने के नोटिस भेजे गए हैं। उक्त कालेज एक माह के अंदर नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो बीयू उनकी संबद्धता समाप्त कर देगा। इसके चलते वे आगामी सत्र 2021-22 में प्रवेश देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की काउंसलिंग में भागीदारी नहीं कर पाएंगे।

प्रदेश टुडे एजुकेशन

विवि ने संबद्धता समाप्त करने भेजे नोटिस

सूबे के आठ जिलों में बीयू से संबद्धता प्राप्त 280 निजी कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन और प्राचार्यों का काफी फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसका खुलासा करने के लिए बीयू ने सभी 280 निजी कालेजों को नोटिस भेजा है। इसमें कालेज संचालकों को अपने कालेज में पदस्थ प्राचार्य, एचओडी और प्रोफेसरों की पूरी जानकारी भेजना है, क्योंकि निजी कॉलेजों में विद्यार्थियों ने प्रवेश तो लिया है, लेकिन उनको नियंत्रित करने वाले प्राचार्य, एचओडी और अध्ययन कराने वाले प्रोफेसर ही नियुक्त नहीं हैं।

यहां तक यूजीसी के मापदंडों के मुताबिक विद्यार्थियों के रेशे में प्रोफेसरों को नहीं रखा गया है। ऐसे कालेजों की संबद्धता समाप्त करने नोटिस भेजे गए हैं। कालेजों को एक माह के अंदर नोटिस का जवाब भेजना है।

प्रोफेसर छोड़ चुके हैं नौकरी

प्रोफेसर निजी कॉलेजों में नौकरी छोड़ चुके हैं। वेतन ज्यादा होने के कारण कालेज संचालकों ने उन्हें बाहर कर दिया है। और कम वेतन में दूसरे व्यक्ति को रख लिया है। कालेज संचालकों ने दोनों प्रकरणों की सूचना बीयू को नहीं भेजी है। वहीं प्राचार्य कालेजों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद भी कालेज उनका नाम दस्तावेजों में चला रहे हैं। यूजीसी के मापदंडों के मुताबिक कोड 28 तहत नियुक्ति कराने में प्रोफेसरों को लाखों रुपए का वेतन देना होगा।

1 माह का दिया समय

कालेजों में प्रोफेसर, एचओडी और प्राचार्यों ही नहीं हैं। कालेजों में वास्तविक से अवगत होने के लिए नोटिस दिए गए हैं। कॉलेज समयसीमा में नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, तो नियमानुसार उनकी संबद्धता समाप्त की जाएगी।

दैनिक भास्कर भोपाल 30-04-2021

भास्कर नॉलेज सीरीज गरम पानी में नींबू का रस, ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का और छुहारे लेना अच्छा

पुरुषों का हीमोग्लोबिन 14 और महिलाओं का 12 से कम हो तो इम्यूनिटी कमजोर, संतरा-अन्नानास जैसे फल लें; रोज कसरत जरूरी

भास्कर एक्सपर्ट

डॉ. तरुण साहनी
सीनियर कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल

बाजार में कई इम्यूनिटी बूस्टर, मगर इनकी सत्यता जांचना संभव नहीं...बेहतर है खान-पान पर ध्यान दें

कोरोनाकाल में लोगों ने संभवतः जो टर्म सबसे ज्यादा सर्च किया है वह है, इम्यूनिटी। सब जानना चाहते हैं कि इम्यूनिटी का स्तर क्या है और कैसे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं विषयों पर दैनिक भास्कर के **पवन कुमार** ने विशेषज्ञ से बात की। जानिए क्या है विशेषज्ञ की राय...

• इम्यूनिटी का सही मतलब क्या है?

मानव शरीर में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। कुछ शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं जबकि कुछ नुकसानदेह। ऐसे अवयव जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं, शरीर के अंदर के वायरस से लड़ने की शक्ति पैदा करते हैं, उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है।

• क्या यह जानने का कोई तरीका है कि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी का स्तर क्या है?

हां। अलग-अलग बीमारियों के प्रति इम्यूनिटी जांचने के लिए अलग-अलग टेस्ट होते हैं। कोरोना के केस में आईजीजी एंडीबॉडी टेस्ट से इम्यूनिटी पता चलती है। सामान्य तौर पर हीमोग्लोबिन के स्तर से इम्यूनिटी पता कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का आदर्श स्तर पुरुषों में 16 और महिलाओं में 14 होता है। यदि पुरुषों में हीमोग्लोबिन 14 से और महिलाओं में 12 से कम हो तो मान सकते हैं कि इम्यूनिटी कमजोर है।

• क्या किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कुछ ही दिनों में बढ़ाई जा सकती है?

हां। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने का कृत्रिम तरीका बहुत स्थायी हीं होता है। दवा व अच्छे खान-पान से कुछ दिनों में इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं।

• कहा जा रहा है बच्चों की इम्यूनिटी ज्यादा है, क्या ये सही है? यदि हां, तो ऐसा क्यों होता है?

बच्चों में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, यह सही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों में संक्रमण नहीं होता। बच्चे कई तरह के संक्रमण को रिसीव ही नहीं कर पाते, लिहाजा बचे रहते हैं।

• बाजार में हर प्रोडक्ट यह कह कर बेचा जा रहा है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें सच्चाई है?

बाजार में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जरूर मिलते हैं जो फूड सप्लीमेंट के तौर पर अच्छे होते हैं और वास्तव में उससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन सत्यता जांचना बहुत जरूरी है जो हर बार संभव नहीं होती। लिहाजा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाजरा, चना और मूंग, दाल, हरी सब्जी और दूध का सेवन ज्यादा कारगर होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए केले और सिट्रस फल जैसे संतरे, अन्नानास आदि लेने चाहिए। गरम पानी के साथ नींबू का रस अच्छा होता है। लहसुन भी इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर होता है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, मुनक्के और छुहारे ले सकते हैं।

• सिर्फ खान-पान से इम्यूनिटी सुधार सकते हैं?

सिर्फ खान-पान से इम्यूनिटी में सुधार नहीं होगा। सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, 7-8 घंटे की गहरी नींद लेनी होगी। तनाव घटाना होगा। इसके साथ पौष्टिक आहार से इम्यूनिटी सुधरेगी।

कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ज्यादा सावधानी अभी जरूरी

शेष भाग | पेज 12 पर

यूजी-पीजी फाइनल परीक्षा की तारीख तय नहीं

ओपन बुक पद्धति : शासन के आदेश का इंतजार, 15 जून बाद तक नहीं आसार

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। बढ़ते संक्रमण के चलते यूजी-पीजी कोर्स की आफलाइन परीक्षा निरस्त हो चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग ने फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का मूल्यांकन ओपन बुक पद्धति से करने का फैसला लिया है। मगर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) ने संक्रमण की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए परीक्षा की तारीख निर्धारित नहीं की है। अधिकारियों के मुताबिक शासन से आदेश मिलने के बाद परीक्षा का कार्यक्रम बनाया जाएगा। वैसे 15 जून तक ओपन बुक पद्धति से भी परीक्षा होना संभव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि विश्वविद्यालय अगले कुछ दिनों में उच्च शिक्षा विभाग से परीक्षा-रिजल्ट के मुद्दे पर मार्गदर्शन ले सकता है।

बीए, बीकाम, बीएससी फाइनल ईयर और एमए, एमकाम व एमएससी फाइनल सेमेस्टर की ओपन बुक पद्धति से परीक्षा करवाई जानी है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए पेपर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जाता है कि मई के पहले सप्ताह तक सभी विषयों के ओपन बुक पद्धति से पेपर बन जाएंगे। मगर प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड अभी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ओपन बुक पद्धति से परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन नहीं आई है। माना जा रहा है कि मई के तीसरे सप्ताह तक आने की उम्मीद है। वैसे विश्वविद्यालय प्रशासन भी संक्रमण कम होने तक परीक्षा करवाने पर विचार नहीं कर रहा है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 15 जून तक परीक्षा को लेकर कोई आसार नजर नहीं आ रहे है, लेकिन अधिकारियों ने पेपर अपलोड करने के बाद 20-25 दिन में रिजल्ट देने की योजना बनाई है। इस बारे में 10 मई के बाद मूल्यांकन केंद्र को बताया जाएगा। परीक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि परीक्षा से पहले कालेजों को विद्यार्थियों के सीसी नंबर भेजना है।

आज का इतिहास

1870 दादा साहब फाल्के - भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता-निर्देशक एवं पटकथा लेखक का जन्म हुआ।

1837 हरि सिंह नलवा - महाराजा रणजीत सिंह के सेनाध्यक्ष का निधन हुआ।

2010 हिन्दी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देव आनंद को मुंबई में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से तथा प्राण को फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया।

2008 चालक रहित विमान लक्ष्य का उड़ीसा के बालासोर जिले के चाँदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

2007 नेत्रहीन पायलट माइल्स हिल्टन ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकार्ड बनाया।